

; k=k HÜk fu; e
¼foRr h gLr i¶Lrdk [k M&3½

यात्रा भत्ता से संबंधित नियम वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 में दिये गये हैं। पांचवे वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने के पश्चात शासनादेश संख्या सा- 4-395/ दस 99-600/99 दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा यात्रा भत्ता की दरों को पुनरीक्षण हेतु आदेश जारी किये गये था। छठवें वेतन आयोग की संस्तुति पर उत्तराखण्ड भासन के कार्यालय ज्ञाप 411/XXVII(7)/2010, दिनांक 2010 द्वारा दरों का पुनरीक्षित कर दिया गया है।

l kkl fu; e %

1. परिवार का तात्पर्य पति/पत्नी, वैधानिक बच्चों (गोद लिया गया बच्चा सहित), सौतेले बच्चों से हैं, जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हो तथा उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हों। स्थानान्तरण तथा अन्य सभी यात्रा के लिए सरकारी कर्मचारी के साथ रहने वाले तथा उस पर पूर्ण रूप से आश्रित उसके माता-पिता, अविवाहिता बहनें और अवस्यक भाई, भी परिवार में सम्मिलित है।

(नियम 6)

2. गोद ली गई सन्तान की बैध (धर्मज) सन्तान माना जायेगा, यदि शासकीय सेवक ने लागू वैधानिक विधि से गोद लिया हो। परन्तु शासकीय सेवक की उन धर्मज पुत्रियां, सौतेली पुत्रिया तथा बहनों को उस पर आश्रित नहीं माना जायेगा जिनका गौना या रुखसत हो चुका हो।

3. यात्रा भत्ता एक प्रतिकर भत्ता है। इसको इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए कि यह कुल मिलाकर प्राप्तकर्ता को लाभ का साधन न हो।

4. राजकीय सेवक को देय तिथि के एक वर्ष पश्चात यात्रा भत्ता के लिए प्रेषित दावा को कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

¼fu; e &74¼hfo0fu0l 0 [k M&5] Hkx&1½

5. पूर्णगामी प्रभाव से पदोन्नति होने अथवा वेतन की दर में वृद्धि स्वीकृत किये जाने के कारण यात्रा भत्ता दावे का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं है।

¼fu; e 12½

6. यात्रा प्रारम्भ तथा समाप्त होने के बिन्दु के लिए आधार निम्नवत होता है :-

(क) यात्रा के प्रारम्भ व अन्त के स्थान पर यदि जिलाधिकारी का कार्यालय है और यात्रा के प्रारम्भिक बिन्दु अथवा अन्तिम बिन्दु की दूरी रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन से 8 कि०मी० से अधिक नहीं है, तो यात्रा का प्रारम्भ अथवा अन्त का स्थान जिलाधिकारी का कार्यालय माना जायेगा। यह दूरी परिशिष्ट पांच में प्रत्येक जिला मुख्यालय के लिए दर्शयी गयी है। दिल्ली में यथा स्थान उत्तरांचल निवास माना गया है।

(ख) यदि उस स्थान में जिलाधिकारी का कार्यालय नहीं है अथवा वास्तविक प्रारम्भिक/अन्तिम बिन्दु (चाहे वह सरकारी सेवक का निवास स्थान हो अथवा कार्यालय हो) तथा रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन की दूरी 8 कि०मी० से अधिक हो, तो यात्रा का प्रारम्भ व समाप्ति का स्थान ही वास्तव में यात्रा प्रारम्भ अथवा समाप्त करने का स्थान माना जायेगा।

¼foRr h gLr i¶Lrdk [k M&3]fu; e 14½

7. मुख्यालय से 8 कि०मी० के अन्दर या नगर निगम की सीमा जो भी अधिक हो की गयी यात्राओं के लिए साधारणतः कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होता है परन्तु फ़ैरी, टोल या रेल भाडा आदि का वास्तविक व्यय लिया जा सकता है।

¼foRr h gLr i¶Lrdk [k M&3]fu; e 26½

8. एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण की दशा में सरकारी सेवक का वर्गीकरण उन दोनों में से निचले पद के संदर्भ में किया जाता है।

(foRr h gLr i¶Lrdk [k M&3]नियम 19)

9. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को शासकीय कार्यवश यात्रा के लिए नियमित राजकीय सेवकों को देय दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता ग्राह्य है। जिस माह में यात्रा की जाती है उसके लिए अन्तिम रूप से देय दैनिक वेतन को यात्रा भत्ते की प्रदेयता हेतु आधार माना जायेगा।

(नियम - 21 सी)

2. अनुषंगिक व्यय निम्न शर्तों के अधीन देय है :-

निःशुल्क वाहन से यात्रा करने पर सरकारी सेवक को नियमानुसार अनुमन्य दर पर अनुषंगिक व्यय निम्न शर्तों के अधीन देय है :-

1. उस दिन के लिए दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होता हों।
2. अनुषंगिक व्यय के धनराशि साधारण दर पर अनुमन्य एक दिन के दैनिक भत्ते से अधिक नहीं होगी,
3. ऐसी दशा में जहां अवस्थान आठ घंटे या उससे अधिक होता हो, वहां पर एक दिन का दैनिक भत्ता (उस स्थान के संदर्भ में) या अनुषंगिक व्यय (जिसकी धनराशि साधारण दर पर अनुमन्य एक दिन के दैनिक भत्ते से अधिक नहीं होगी) दोनों में से एक को कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से ले सकता है। परन्तु किसी भी दशा में दैनिक भत्ता तथा अनुषंगिक व्यय दोनों अनुमन्य नहीं होंगे।

3. रेल अथवा बस से जुड़े हैं, वहां की यात्रा केवल रेल अथवा बस से ही की जानी चाहिये। इसके बावजूद कुछ स्थानों के बीच में रेल अथवा बस से यात्रा करना सार्वजनिक हित में नहीं होता है, जैसे समय की बचत अथवा रास्ते में कार्य का निरीक्षण आदि। ऐसी स्थिति में यदि नियंत्रक अधिकारी सन्तुष्ट हो कि ऐसी यात्रा शासकीय कार्य के हित में थी तो राजकीय सेवक नियम-23 बी (2) के अन्तर्गत देय सड़क भत्ता पाने का अधिकारी होगा। ऐसे मामलों में नियंत्रक अधिकारी बस के स्थान पर सड़क से इस प्रकार की यात्रा किये जाने का कारण उल्लेख करते हुए यात्रा भत्ता बिल पर प्रमाण-पत्र देंगे।

(नियम - 14ए (3) तथा स्पष्टीकरण)

ऐसी यात्राओं के संबंध में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सड़क किलोमीटर भत्ते की निम्न दरें निर्धारित की गई :-

4. मोटर कार, मोटर कैरियर या जीप/कार से की गई सड़क यात्राओं के लिए:-

		रु० प्रति कि०मी०	रु० प्रति कि०मी०
		i) पथ पर	ii) पथ पर
1	प्रथम 500 कि०मी० तक तय की गयी दूरी के लिए	4.50	3.50
2	500 कि०मी० से अधिक परन्तु 1200 कि०मी० तक की गयी दूरी के लिए	3.25	2.75
3	1200 कि०मी० (एक माह) से अधिक तय की गयी दूरी के लिए	शून्य	
(ख)	उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/ डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साइकिल/ स्कूटर इत्यादि से की गई सड़क यात्राओं के लिए	रु० 2:00 प्रति कि०मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिए रु० 400 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।	

(ग)	पेट्रोल / डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिए	रु0 0:60 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु0 120 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।
-----	---	---

c& #010|000¼gkus orueku ds vuđ kj ½ i frekg l s de oru i kusokys l j d kj h l od %

(क)	पेट्रोल / डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिए	रु0 2:00 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिए रु0 400 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ख)	पेट्रोल / डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिए	रु0 0:60 प्रति कि0मी0 इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिए रु0 120 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।

यात्रा पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थानों से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन अथवा रेलवे स्टेशन के बीच की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिए समस्त शासकीय सेवको को रु0 4 प्रति कि0मी0 की दर से सड़क कि0मी0 भत्ता ग्राह्य होगा। इस प्रयोजन हेतु दूरी की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -3 के नियम 14 सपटित परिशिष्ट -5 के आधार पर की जायेगी।

नियम - 23 (बी)(3)

fVli . kh % प्रदेश के पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले शासकीय सेवक उपर्युक्त सड़क किलोमीटर भत्ता दरों पर 33-1/3 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार। पर्वतीय स्थानों से तात्पर्य नियम -11-ए मते उल्लिखित क्षेत्र से है।

नियम -23 (बी) (2) अपवाद-1

4& nšud HÜk

सरकारी सेवक को राजकीय कार्य से अपने मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थान पर 8 घंटे या अधिक अवस्थान करने पर उस दिन के लिए नियम 27(ए)(ए)(11) तथा 27(बी)(1)ए(11) के अधीन नियम 23 (सी) (1) में निर्धारित दर पर नियम -27 (डी) के उपबन्धों के अन्तर्गत दैनिक भत्ता ग्राह्य होता है।

नियम -23 (सी)(1)

सरकारी सेवक को अवस्थान की अवधि में निःशुल्क भोजन व आवास दोनों सुविधा उपलब्ध होने पर दैनिक भत्ते की अनुमन्य दर 1/4 की दर से तथा दोनों में से कोई एक सुविधा उपलब्ध होने पर अनुमन्य दर के लिए 1/2 की दर से दैनिक भत्ता ग्राह्य होता है।

नियम -23 (सी)(घ)

नियम 23 बी 4 अपवाद

5& अपने चार्ज के सरकारी वाहन कार, जीप आदि से मुख्यालय से वाहर सड़क द्वारा की गई यात्रा के लिए ड्राइवर आनुषंगित भत्ता पाने के लिए अधिकृत होंगे। मुख्यालय से कम से कम एक रात्रि की अनुपस्थिति में साधारण दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी यात्रा में यदि मुख्यालय से बाहर किसी स्थान पर 8 घंटे अवस्थान शामिल हो तो इसे दैनिक भत्ते के स्थान पर उसके लिए नियम 27 (बी)-1ए -11 के अधीन दैनिक भत्ता लिया जा सकता है। स्थानीय यात्राओं के लिए कोई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

नियम 29 अपवाद

7& nšud HÜk dh vuđU rk esfo'kk l fo/kk %

1. यात्रा के दौरान जब सामान्य रूप से उस तिथि / तिथियों के लिए दैनिक भत्ता अनुमन्य न हो तो शासकीय सेवक निम्न दशाओं में एक दिन का साधारण दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा:-

(क) शासकीय कार्यवश गन्तव्य स्थान पर पहुंच कर दो तिथियों में मिलकर 8 घंटे या उससे अधिक का रात्रि अवस्थान हुआ हो या

- (ख) शासकीय सेवक को यात्रा के दौरान रात्रि में अगली बस, रेल या वायुयान की प्रतीक्षा में 4 घंटे या उसे अधिक अवस्थान करना पड़े।

नियम -27(सी)(2)

शासकीय ज्ञाप सं. सा -4-1359/दस -86-602/81, दिनांक : 30.8.86

8& n&ud H&ks dh vu&U vof/k %&

सरकारी सेवकों को मुख्यालय से बाहर प्रशिक्षण की अवधि में दैनिक भत्ता निम्न अवधि के लिए ग्राह्य है:-

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. प्रथम 45 दिन तक | पूरी दर पर |
| 2. अगले 135 दिन तक | आधी दर पर |
| 3. कुल 180 दिन के बाद | शून्य |

प्रशिक्षण के मामलों में प्रशिक्षण अवधि 180 दिन से अधिक होने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को यह विकल्प होगा कि वह चाहे तो प्रशिक्षण अवधि में उपयुक्तानुसार दैनिक भत्ता ग्रहण करें अथवा केवल स्वयं के लिए स्थानान्तरण पर अनुमन्य भत्ता लें। स्थानान्तरण का यात्रा भत्ता ग्रहण करने की दशा में उसे प्रशिक्षण अवधि में कोई दैनिक भत्ता ग्राह्य नहीं होगा।

नियम 27 (डी)(3)

सरकारी कार्यवश दौरे के सम्बन्ध में पूर्ववत् किसी स्थान पर अवस्थान के लिए 10 दिन तक ही पूरी दर पर दैनिक भत्ता देय है। दौरे की अवधि किसी स्थान पर 10 दिन से अधिक होने पर नियम 27 (डी) के अन्दर छूट दिये जाने पर ही दैनिक भत्ता प्रथम 30 दिन पूरी दर पर तथा 30 दिन पश्चात् 150 दिन तक आधे दर पर देय होगा। 180 दिन के पश्चात् दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

नियम 27 (डी)

viokn%&

किसी स्थान पर अवस्थान की निरन्तरता तब तक बनी रहती है जब कि वह 8 कि०मी० से दूरस्थ स्थान पर 5 दिन से अधिक की अवधि के अवस्थान द्वारा भंग न हुई हो।

यदि सरकारी सेवक अवकाश पर गया हो तो निरन्तरता तब तक भंग नहीं मानी जायेगी जब तक अवकाश पर अनुपस्थिति की अवधि 14 दिन से अधिक न हो।

नियम 27(डी) नोट-2 तथा 2ए

LF&ku&rj . k ; k=k H&U&k

1- , d eqr LF&ku&rj . k vu&ku %dEi k&t V V&U Qj x&U&V 1/2

कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट प्रदेश के शासकीय सेवकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में देय होगा तथा इसमें अब तक मिल रहे पैकिंग भत्ता, आवास से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के लिए सड़क मील भत्ता एवं सरकारी सेवकों तथा उसके परिवार के सदस्यों को स्थानान्तरण पर यात्रा की दशा में मिलने वाले आनुषंगिक व्यय को समाहित माना जायेगा अर्थात् कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट अनुमन्य होने पर उपरोक्त भत्ते देय नहीं होगा।

यदि यात्रा स्वयं अकेले की गई हो :-

यदि स्थानान्तरण के अवसर पर सरकारी सेवक ने स्वयं ही अकेले यात्रा की हो, तो उस स्थिति में उल्लिखित भार के 2/3 भाग तक की अधिकतम सीमा तक के व्यक्तिगत समान की ढुलाई का व्यय ही देय होगा।

यदि कोई सेवक उपरोक्त मात्रा से अधिक सामान सस्ते मार्ग से ले जाता है अथवा मालगाडी के स्थान पर यात्री गाडी अथवा ट्रक से ले जाता है, तो वह उपरोक्त मात्रा को मालगाडी से ओनर्स रिस्क पर सामान्य मार्ग से ले जाने के लिए देय धनराशि की सीमा तक उसके द्वारा किया गया वास्तविक व्यय अनुमन्य होगा।

नियम -42(2)(1)

4. अतिरिक्त वाहन रखने का पात्र शासकीय

उपरोक्त मात्रा तक सामान ढोने के व्यय के अतिरिक्त वाहन रखने का पात्र शासकीय सेवक मोटर कार, स्कूटर/मोपेड/साइकिल को रेल से ओनर्स-रिस्क पर ले जाने के वास्तविक व्यय (कार के लिए ड्राइवर के यात्रा व्यय सहित) की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। मालगाडी से जाने की दशा में वह पैकिंग चार्ज तथा पुराने स्थान तक तथा नये स्थान पर स्टेशन से घर तक ले जाने का व्यय आहरित कर सकता है, परन्तु वह कुल धनराशि उस वाहन की यात्री गाडी से ले जाने के लिए देय धनराशि से अधिक नहीं होगी।

नियम-42(2)(1)(1) तथा टिप्पणी-2

शासकीय सेवक यदि वाहन को रेल से जुड़े दो स्थानों के मध्य सड़क से ढोता है तो वह वास्तविक ढोलन व्यय को रेल से ओनर्स रिस्क पर ढोने की दशा में अनुमन्य धनराशि की अधिकतम सीमा के अधीन प्राप्त कर सकता है, परन्तु मोटर कार/मोटर साइकिल/मोपेड को उसकी अपनी शक्ति से चलाकर सड़क द्वारा ले जाता है तो क्रमशः 35 पैसे तथा 15 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से परिवहन व्यय आहरित कर सकता है। यदि वे स्थान रेल द्वारा नहीं जुड़े हों तो उपरोक्त 35 पैसे तथा 15 पैसे प्रति कि०मी० की दर सीमा तक सड़क से ले जाने का वास्तविक व्यय आहरित कर सकता है।

नियम-42(2) (1) तथा (2)

5. निजी सामान की स्थानीय ढुलाई के लिए ठेके

निजी सामान की स्थानीय ढुलाई के लिए ठेके के स्थान पर अब निजी सामान के परिवहन हेतु मालगाडी से स्वयं के जोखिम पर अनुमन्य ढुलाई व्यय का 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय अनुमन्य होगा।

नियम 42(2)(11)(111) तथा (1)

यह आवश्यक नहीं है कि राजकीय सेवक के परिवार के सदस्य उसके साथ यात्रा करें तथा निजी सामान और वाहन उसके साथ ले जायें। यदि वह उसके कार्यभार से मुक्त होने की तिथि से एक माह से अनाधिक अवधि पूर्व अथवा बारह माह से अनाधिक अवधि के पश्चात ले जाये जाते हैं तो उनके लिए यात्रा/यातायात व्यय का भुगतान देय है।

नियम 42(2)(11) टिप्पणी-2

6. अस्थायी स्थानान्तरण का अर्थ

अस्थायी स्थानान्तरण का अर्थ 180 दिन से अनाधिक अवधि के लिये किये गये स्थानान्तरण से है। ऐसे स्थानान्तरण के लिए मुख्यालय से अस्थायी स्थानान्तरण के स्थान (अस्थायी मुख्यालय) को जाने तथा वहां से मुख्यालय वापस आने के लिए की गई यात्रा दौरे पर की गई यात्रा समझी जायेगी तथा राजकीय सेवक उनके लिए यात्रा भत्ता नियमों के अधीन सामान्य दर पर माइलेज तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रकार के मामले में कार्यभार ग्रहण काल अनुमन्य नहीं होगा। वास्तविक समय दौरे की यात्रा की भांति अनुमन्य होगा।

नियम 42(2) टिप्पणी -21

7. शासन की स्पष्ट अनुमति के बिना नियंत्रक अधिकारी यात्रा बिल पर प्रति हस्ताक्षर करने का अधिकार

किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनिधायन नहीं कर सकते।

नियम (91)

mRrjk[k M 'Hd u ds dk lzy; Kki l d; k 78@XXVII%2009] fnukd 01
ekp% 2009 rFkk dk lzy; Kki l d; k 411 XXVII%2010] fnukd 06 tuojh
2010 ds }kj k NBos oru vk l dh l rfr in ; k=k Hrk dh njk dk iujh{k k
fd; k x; k gS% Dyhd dj%

मंत्रालय 'क' उ
फॉक वुडक&3

संख्या-1422गगअपप(3)स्था.या.भ./2004

लखनऊ : दिनांक 27 अक्टूबर, 2004

दक क्य; क्कि

फो"क & व्फ[ky क्किरह लोक ds vf/कdfj; क ds fy, , d eqr LFकुर्ज.k
वुक्कु ds fo"क; eaQ oLFKA

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के केन्द्र सरकार से राज्य सरकार में आने पर यदि अन्यथा नियमों में व्यवस्था न की गई हो, तो राज्य सरकार के स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के नियम लागू होने की व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनु-4 के कार्यालय ज्ञाप सं0-सा-4-395/दस-99-600/99 दिनांक 11 जून, 1999 के बिन्दु 11(ब) में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट के रूप में सम्बन्धित सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वेतन, अधिकतम रू0 10,000/= की सीमा के अधीन धनराशि अनुमन्य की गई है, लेकिन अन्य प्रदेश से अथवा भारत सरकार में प्रदेश के अन्दर आने वाली यात्राओं के विषय में कोई स्पष्ट नहीं है।

अतः इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष परिस्थितियों में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भारत सरकार या अन्य राज्यों से आने एवं जाने पर भारत सरकार में लागू स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की दरें अनुमन्य करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 जून, 1999 के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के नियम लागू रहेंगे तथा उक्त सीमा तक स्थानान्तरण यात्रा भत्ता सम्बन्धी भुगतान संशोधित समझा जाय, परन्तु जिन प्रकरणों में भुगतान किया जा चुका है उसे पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

राधा रतूड़ी
सचिव।